प्राक्कथन

गत वर्ष देश के कुछ भागों में उत्पन्न हुई सूखे जैसी स्थिति के कारण कृषि के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुईं, लेकिन प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली द्वारा समय पर दिए गए परामर्शों से किसानों को इस स्थिति से निपटने में सहायता मिली। वर्ष के दौरान हुआ रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन परिषद के अंतर्गत इसके संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की सफलता का प्रमाण है जिससे कृषि वृद्धि तथा सक्षम मानव संसाधन विकास में उल्लेखनीय योगदान हुआ है। भारत ने हाल ही में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर के साथ खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, दूध, अंडे और मछलियों का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है।

विभिन्न निवेशों में से गुणवत्तापूर्ण बीज तथा रोपण सामग्री कृषि की सफलता के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। इस प्रयास में देश के विविध कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों की 90 से अधिक उन्नत किस्में/संकर विकसित किए गए तथा लगभग 9840 टन प्रजनक बीज और 40 मिलियन रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया, ताकि विभिन्न राज्यों की मांग को पूरा किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण गन्ने के त्वरित प्रगुणन और इसके साथ-साथ प्रति इकाई क्षेत्र में बीज गन्ना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गन्ना कलिका-चिप प्रौद्योगिकी विकसित की गई। अरहर का एक अनूठा माइक्रोसेटेलाइट डेटाबेस (Pipemicrodb) तैयार किया गया (http://cabindb.iasri.res.in/pigeonpea/)। प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और दक्ष प्रबंधन के लिए जल की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु एक नवीन भूजल बंटवारा मॉडल विकसित किया गया।

भा.कृ.अ.प. की नस्ल पंजीकरण समिति ने गोपशु की 9 नई नस्लों को मान्यता प्रदान की है और इस प्रकार अब पंजीकृत देसी पशुधन नस्लों की संख्या 144 हो गई है। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार डिम्ब पिक-अप तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए होली नामक मादा साहीवाल बछिया का जन्म कराया है। इस तकनीक में बांझ तथा अधिक आयु के डेरी गोपशुओं के जननद्रव्य का सफल उपयोग करने की क्षमता है। भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हिम परिरक्षित भ्रूण से मोहन नामक मिथुन बछड़े का जन्म कराने में पहली सफलता प्राप्त की गई। रिंडरपेस्ट के निर्मूलन पर की गई वैश्विक पहल में सक्रिय भागीदारी तथा गहन अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों के माध्यम से भारत को पशुधन के इस घातक रोग से मुक्त देश घोषित किया गया है।

कृषि शिक्षा एवं मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास में पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण, डिज़िटल पुस्तकालयों के निर्माण और शिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श में उत्कृष्टता प्रदान करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों को सबल बनाने का कार्य जारी रहा। कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के लिए कुल 327 ई-पाठ्यक्रम मॉड्यूल (ई-अधिगम प्लेटफार्म) विकसित किए गए।

वर्ष के दौरान पांच नए कृषि विज्ञान केन्द्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, प्रत्येक में 1-1, स्थापित किए गए। इस प्रकार पूरे देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों की कुल संख्या 631 हो गई है। जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल (निक्रा) के अंतर्गत देश के 100 संवेदनशील जिलों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किए गए। वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए वांछित ज्ञान और निपुणता में सुधार हेतु कृषकों व विस्तार कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ज्ञान में भागीदारी के एक त्वरित तथा प्रभावी मोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति का उपयोग करने के लिए परिषद के ई-प्रकाशन मंच ने अनुसंधान प्रकाशनों की ऑन-लाइन उपलब्धता की सुविधा प्रदान की है जिसका लाभ विश्व के 180 से अधिक देश उठा रहे हैं। इसी प्रकार, देश में कृषि ज्ञान प्रबंध प्रणाली को सबल बनाने के लिए जैव-सूचना विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के आवेदनों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ग्रिड (एनएबीजी) विकसित किया गया। वर्तमान बौद्धिक सम्पदा अधिकार या आईपीआर के युग में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सृजित प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के लिए 96 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए।

कृषि अनुसंधान एवं विकास में भा.कृ.अ.प. के अंतरराष्ट्रीय सहयोग संबंधी क्रियाकलापों को कृषि एवं वानिकी पर दूसरी एएसईएएन-भारतीय मंत्रालयीन बैठक, बीआरआईसीएस कृषि विशेषज्ञ परामर्श, सीजीआईएआर-आईएसपीसी मीट, खुरपका एवं मुंहपका रोग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सीमा पार के रोगों पर भा.कृ.अ.प.-'अपारी' विशेषज्ञों के परामर्श, कृषि में विविधीकरण पर तृतीय अंतरराष्ट्रीय सस्यविज्ञान कांग्रेस, जलवायु परिवर्तन प्रबंध तथा आजीविका सुरक्षा और भारतीय-एएसईएएन कृषक विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से सबल बनाया गया। वर्ष के दौरान अफ्रीका फोकस पर चल रही पहलों को 15 अंतरराष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रदान कर तथा अफ्रीकी नागरिकों के लिए अध्ययन दौरे आयोजित कर और अधिक शक्ति दी गई। भा.कृ.अ.प. व सीजीआईएआर के दो संस्थानों, नामत: इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तथा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कार्य योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

यह अनुभव किया जा रहा है कि निकट भविष्य में भारत को सार्वजनिक तथा निजी निवेश को वर्तमान 0.7% से 1% तक बढ़ाना होगा तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ताकि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में टिकाऊ विकास हो सके। भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे अनुसंधान एवं सक्षम मानव संसाधनों के नियोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नई पहलें शुरू की गईं हैं तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के संदर्भ में परिदृश्य 2050 के दस्तावेजों के मसौदे तैयार किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि *डेयर/भा.कृ.अ.प.* की वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 कृषि में टिकाऊ वृद्धि के लिए भावी नीतियां तैयार करने व योजना बनाने में एक उपयोगी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी।

(शरद पवार)
अध्यक्ष
भा.कृ.अनु.प. सोसायटी